There is at present about 9.6 per cent shortage in the availability of power to meet the requirments. The steps taken by the Government to meet this and other energy shortages include, *inter alia* expediting commissioning of new capacity in the different energy sectors, implementing short gestation projects, reducing transmission and distribution losses, implementation of energy conservation and demand management and arranging transfer of energy from surplus to deficit States.

Price control on Pharmaceuticals

1906. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have implemented into to the scheme of price control on all pharmaceuticals items in the country;

(b) if the answer to part (a) above be in the negative, what are reasons therefor and what action Government have taken to avoid speculative business in pharmaceutical industry; and

(c) whether it is a fact that the drug items have been classified wrongly?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETRO-CHEMICALS IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI R. K. JAICHANDRA SINGH): (a) Government have implemented the various provisions of Drugs (Prices Control) Order, 1979 with a view to control prices of bulk drugs and formulations covered under the Drugs (Prices Control) Order, 1979.

(b) Does not arise.

(c) Drug manufacturing units are required to classify the formulations in their price list according to the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 1979. Centain cases of wrong categorisation have come to the notice of the Government and appropriate action has been taken in such cases.

गैर - परम्परागत ऊर्जा

1907. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोबर, गैस, नये चूल्हों, सौर ऊर्जा मीनारों तथा तालाबों और पवन ऊर्जा के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है और "योजना" पत्रिका के अक्टूबर,1986 के अंक 8 में प्रकाशित लेख पर विभाग की प्रतिक्रिया क्या है ;

(ख) गोबर गैस और बायोगैस में क्या अन्तर है और इन क्षेत्रों में कितनी सफलता मिली है उनकी उपयोगिता क्या है और इस प्रयोजन के लिए केन्द्र द्वारा राज्यों को कितनी सहायता अनुदान राशि दी जा रही है ;

(ग) क्या निःशुल्क शौचालयों को अनिवार्यतः इसमें जोड़ने के लिए कोई व्यवस्था की जा रही है क्योंकि इससे इसकी उपयोगिता बहुप्रयोजनीय हो जाएगी ; और

(घ) इस के संबंध में अनुसंधान कार्य की क्या स्थिति है और इसकी प्रक्रिया के सरलीकरण, इसकी लागत में कमी किए जाने पर इसकी उपयोगिता बढ़ाये जाने के कार्य में कितनी सफलता मिली है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) (क) अद्यतन सूचना निम्न प्रकार से है :—

मद	अब तक स्थापित किए एककों की संख्या
परिवार आकार बायोगैस (गोबर गैस) संयंत्र	6.5 लाख
सामुदायिक और संस्थागत बायोगैस संयंत्र	198
उन्नत प्रकार के चूल्हे	22 लाख
पवन ऊर्जा फार्म	5
पवन चक्कियां (जल पम्पन)	1600

इनके अतिरिक्त, केन्द्रीय मीनार, संकल्पना और सौर तालाब पर भी आधारित सौर तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए परियोजनायें बनाई गई हैं ।

दिनांक 1—15 अक्टूबर, 1986 को "योजना" नामक पत्रिका (मैगजीन) के हिन्दी संस्करण के पृष्ठ 8 और 9 पर ए लेख छपा है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहन-सहन के स्तर को सुधारने में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की महत्वपूर्ण उपयोगिता का वर्णन करता है ।

(ख) गोबर सहित कार्बनिक कूड़ा-करकट से बायोगैस प्राप्त की जा सकती है । गोबर गैस बायोगैस का ही एक किस्म है जबकि इस में गोबर का प्रयोग होता है । इसका प्रयोग खाना बनाने और रोशनी के लिए किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त इसका उपयोग डीजल इंजनों को चलाने एवं विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है । इसके अलावा, बायोगैस संयंत्र अच्छी प्रकार की खाद उपलब्ध कराता है और इसके कई सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं ।

बायोगैस विकास को राष्ट्रीय परियोजना के लिए तथा 1986-87 के लिए सामुदायिक एवं संस्थागत बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम के लिए 66.77 करोड रुपये उपलब्ध किए गये हैं और निर्धारित मानदण्डों के अनुसार, राज्य सरकार को फन्डस उपलब्ध किये गए हैं ।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, जहां सम्भव है और लोगों को स्वीकार्य हो, वहां स्वच्छ शौचालयों को बायोगैस संयंत्रों से जोड़ने के कार्य को बढ़ावा देने के लिए योजना को आरंभ किया गया । यह योजना कार्यान्वयन एजेंसियों को दो वर्षों के रखरखाव की गारन्टी को सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रति संयंत्र 150/- रुपये अतिरिक्त टर्न की जॉब के आधार पर उपलब्ध कराती है ।

(घ) सामुदायिक शौचालयों, स्वच्छ शौचालयों के कनेक्शन, परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों और वाटर जैकेटबायोगैस के साथ जोड़े गये बायोगैस संयंत्रों के विशेष डिजाइनों का विकास किया गया है । प्रणाली को और अधिक सरल बनाने के लिए तथा लागत को कम करने व अच्छी उपयोगिता की दृष्टि से अनुसंधान परियोजनायें कार्याधीन हैं ।

Issue of licences to top companies

1908. SHRI SHANKER SINH VAGHELA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what are the details of Licences/Letters of intent issued to 10 top companies during the last three years;

(b) how many of the projects for which licences etc. were issued have been completed so far;

(c) what was the original cost of the project and escalation in the cost due to delay in implementation; and

(d) the details of increase in cost and reasons for delay in implementation of such projects?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Under the provisions of the Industries (Development & Regulation) Act, a total of 32 letters of intent and 15 industrial licences were granted during the years 1983 to 1985 to the following first ten non-Government, non-financial companies in the country ranked according to their assets in 1984:—

1. Tata Iron & Steel Co. Ltd.
2. Reliance Textile Industries Ltd.
3. Tata Engg. & Locomotive Co. Ltd.
4. Associated Cement Cos. Ltd.
5. Larsen & Toubro Ltd.
6. Century Sqng. & Mfg. Co. Ltd.
7. Gujarat Narmada Valley Ferts. Co. Ltd.
8. I. T. C. Ltd.
9. J. K. Syntheties Ltd.
10. Gwalior Rayon Silk Mfg. & Wvng. Company Ltd.